



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-74/2014-परामर्शी सेवा 2973 (अनु0)

दिनांक : 25/9/2017

प्रेषक,

साकेत कुमार

प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सचिव

विधि विभाग

बिहार, पटना।

विषय:-विधि विभाग से प्राप्त योजनाओं की माह अगस्त, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:-निगम का पत्रांक-2451(अनु0) दिनांक-01.08.2017.

महाशय,

विधि विभाग से अब तक ए0डी0आर0 भवन निर्माण की 09 अद्द योजनाएँ (नालन्दा, बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय, मधेपुरा, जहानाबाद, औरंगाबाद, सीवान एवं बेत्तिया) कुल राशि ₹20.40 करोड़ एवं पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में संयुक्त न्यायालय भवन के निर्माण के लिये ₹45.48 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अदालतगंज, पटना में पटना उच्च न्यायालय के लिये स्टाफ कॉलोनी निर्माण कार्य, छज्जुबाग पटना में बहुमंजिली आवासीय कम्प्लेक्स का निर्माण कार्य, व्यवहार न्यायालय बेत्तिया में 15 कोर्ट बिल्डिंग तथा 180 कैदी हाजत, अनुमंडलीय न्यायालय बगहा में 15 कोर्ट बिल्डिंग, सहरसा व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट बिल्डिंग, व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज में 24 कोर्ट बिल्डिंग, मसौढ़ी पटना में आवासीय क्वार्टर का निर्माण तथा पालीगंज पटना में कोर्ट बिल्डिंग एवं स्टाफ क्वार्टर के निर्माण की योजनाएँ प्राप्त हुई हैं।

विधि विभाग से प्राप्त योजनाओं की माह जून, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है। माह अगस्त, 2017 तक की प्रगति की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

(i) नालन्दा, बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय, मधेपुरा, जहानाबाद, औरंगाबाद, सीवान एवं बेत्तिया में ए0डी0आर0 कोर्ट निर्माण कार्य की योजना में से 08 अद्द (सीवान, बक्सर, मुंगेर, नालन्दा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मधेपुरा एवं बेगूसराय) की योजना पूर्ण की जा चुकी है। बेत्तिया (प0 चम्पारण) में भूतल के छत का ढलाई कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रथम तल का कार्य चल रहा है।

(ii) पटना व्यवहार न्यायालय में संयुक्त न्यायालय भवन के निर्माण कार्य में तृतीय तल का कार्य प्रगति में है।

(iii) अदालतगंज पटना में स्टाफ कॉलोनी निर्माण के लिये कार्य आवंटित किया जा चुका है। पुराने आवासों को खाली कराने की कार्रवाई चल रही है। Environmental clearance प्राप्त हो गया है। आवास खाली होने के उपरान्त dismantling कार्य प्रारम्भ होगा।

(iv) छज्जुबाग पटना के लिये ₹6072.25 लाख का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजी गयी है।

(v) व्यवहार न्यायालय बेत्तिया में 15 कोर्ट एवं हाजत निर्माण के लिये ₹2845.00 लाख, अनुमंडलीय न्यायालय, बगहा में 15 कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के लिये ₹3010.00 लाख, सहरसा व्यवहार न्यायालय कैम्पस में 10 कोर्ट निर्माण के लिये ₹2221.00 लाख, गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में 24 कोर्ट बिल्डिंग निर्माण कार्य के लिये ₹3363.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कार्य प्रगति पर है। व्यवहार न्यायालय गोपालगंज एवं बगहा में कार्य प्रगति पर है।

(vi) मसौढ़ी पटना में आवासीय क्वार्टर निर्माण के लिये नक्शा तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

(vii) पालीगंज पटना में कोर्ट बिल्डिंग के लिये 06 एकड़ भूमि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। साईट ले-आउट प्लान अनुमोदन के लिये भेजा गया है।

